भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 302
19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

मछली निर्यात के लिए ढांचा

302. श्री डी.के. सुरेशः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का मछुआरों को मछली निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु एक ढांचा बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास उक्त ढांचा बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधानों के साथ कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसे देश में कब तक शुरु किए जाने की संभावना है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) मत्स्य निर्यात की सुविधा के लिए सरकार ने सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 द्वारा एमपीईडीए बनाया है । निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एमपीईडीए निर्यातकों को नामांकित करता है, गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करता है और आयातकों के साथ संपर्क स्थापित करता है । वर्तमान में, निर्यातक बंदरगाह और एग्रीगेटर से मत्स्य लाते हैं ।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2020-21 के दौरान, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में, एक प्रमुख योजना आरंभ की है "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) – भारत के मात्स्यिकी क्षेत्र के स्थायी और जिम्मेदार विकास द्वारा नीली क्रांति लाने की एक योजना" जो मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए 20,050 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वाधिक निवेश के साथ वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किए जाने के लिए है । पीएमएमएसवाई में मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग के लिए ई-प्लेटफॉर्म का प्रावधान है। राज्यों को इसके तहत प्रस्ताव देना होगा। उल्लिखित घटकों के लिए 2020-2022 के दौरान, मत्स्यपालन विभाग ने पीएमएमएसवाई के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों के लिए 151.35 लाख रुपये की मंजूरी दी है ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

***